(d) whether implementation of the Second Five Year Plan has been delayed in any case for late sanctioning of the annual estimates, by the State Governments; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister of Planning (Shri S. N. Mishra): (a) Information in this form was not received from the State Governments. Central assistance for each State is reckoned each year in relation to the annual plan and the resources of the Central Government.

(b) and (c). Two statements are laid on the Table of the Lok Sabha. [*See* Appendix III, annexure No. 8]. Statement I indicates the loans and grants sanctioned and estimated to have been disbursed during 1956-57. Statement II relates to the amount allocated so far during 1957-58.

(d) The number of schemes included in the State plans is large and it is not possible to give any definite reply unless information is asked for about a particular project in a State Plan.

(e) Does not arise.

Small Scale Industries in Andhra

917. Shri M. V. Krishna Rao: Will the Minister of **Commerce and Industry** be pleased to state:

(a) whether any programme has been formulated in consultation with the Small Industries Service Institute for the development of Small Scale Industries in Andhra Pradesh during the year 1957-58; and

(b) if so, the nature of the programme?

The Minister of Industry (Shri Manubhai Shah): (a) and (b). The Programme of the Regional Small Industries Service Institute for development of Small Scale Industries in Andhra during 1957-58 includes the establishment of:—

(i) Extension centre for general engineering and Foundry at Vijayawada;

(ii) Extension Centre for Electroplating and Heat Treatment at Hyderabad;

(iii) Workshop for Testing and Servicing at Hyderabad;

(iv) Servicing Centre for Glass beads at Papanayudupet; and

(v) Production Centre for hand tools at Hyderabad.

II. Purchase of additional equipment for the Small Industries Service Institute at Hyderabad, in order to give better technical assistance to small scale units in this area.

III. Help to small units in Hyderabad to obtain sub-contracts from large units, in addition to giving the normal technical assistance.

उत्पादकता

९१८. श्रीमती गंगादेवी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उत्पादकता बढ़ाने के लिये विदेशों से कितने प्रकार की प्राविधिक जानकारी प्राप्त की जा रही है ;

(ख) इस जानकारी को प्राप्त करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ;

(ग) भारतीय उद्योगों को इस प्रकार की जानकारी से अवगत कराने के लिये क्या किया जा रहा है ;

(घ) क्या सरकार को अन्य देशों से इस प्रविधिक जानकारी को प्राप्त करने के लिये कुछ खर्चा करना पड़ता है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार कितना खर्चा हुआ है और किस रूप में ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ङ). राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की स्थापना के एक प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है । यह परिषद् स्थानीय उत्पादकता परिषदों तथा उत्पादकता में रुचि रखने वाले अन्य संगठनों और संस्थाओं के द्वारा देश में उत्पादकता आन्दोलन आरम्भ करेगी । यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् अन्य कार्यों के साथ, विदेशों से उत्पादकता बढ़ाने सम्बन्धी शैल्पिक जानकारी एकत्र करेगी और उसे भारतीय उद्योगों को देगी । यह जानकारी प्रदान करने के लिये प्रकाशन, श्रव्य-दृश्य प्रसार साधन, प्रदर्शनियों, गोष्ठियों तथा भाषणों आदि का प्रयोग किया जायेगा । इसके अतिरिक्त शैल्पिक ज्ञान संग्रह सेवा तथा शैल्पिक ज्ञान वर्द्धन सेवा की स्थापना भी की जायेगी । अपने विविध कार्यों का खर्चा उठाने के लिये राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को सरकार तथा उद्योगों से धन लेना होगा । चूंकि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को स्थापित करने की प्रायोजना अभी विचाराधीन है इसलिये सरकार ने इस पर अभी कुछ भी खर्च नहीं किया है ।

भारी विद्युत उद्योग विकास परिषद्

६१९. **श्रीमती गंगादेवी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लो बोल्टेज सरकट ब्रेकरों की जांच के लिये भारी विद्युत् उद्योग विकास परिषद् ने क्या सुविधायें निकाली है ;

(ख) इन सुविधाओं की व्यवस्था करने में सरकार ने कितना खर्च किया है ;

(ग) उन में कितने निर्माताओं को लाभ हुआ है ; और

(घ) उनको किस प्रकार का लाभ हुआ है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) विकास परिषद् ने सरकार से सिफारिश की है कि बिजली के विभिन्न प्रकार के उपकरणों का परीक्षण करने के लिये पूर्णतः सज्जित प्रयोगशाला स्थापित की जाये । यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है । अंतकालीन उपाय के रूप में परिषद् ने इस संभावना की जांच की कि बंगलौर की इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस में जो साज-सामान है, उसे इस काम के लिये प्रयोग किया जा सकता है या नहीं । लेकिन ज्ञात हुआ है कि यह मुमकिन नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

रासायनिक गूदे का आयात

६२०. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रासायनिक गूदे की कितनी मात्रा किन किन देशों से मंगाई जा रही है ; और

(ख) क्या रासायनिक गूदे के आयात के लिये किसी देश से कोई विशेष समझौता किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) (क) दिसम्बर, १९५६ तक के आयात के आकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि व्यापारिक वर्गीकरण में रासायनिक लुग्दी को अलग से नहीं दिखाया जाता था । जनवरी से अप्रैल, १९५७ तक १०,८०४ टन रासायनिक लुग्दी फिनलैंड स्वीडन, नारवे, जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड तथा आस्ट्रिया से आयात की गयी ।

(ख) जी, नहीं ।

साइकिलें

६२१. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में बनने वाली साइकिलों की किस्म सुधारने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?